

90 लाख बेघरों को चाहिए इंदिरा आवास

राज्य ब्यूरो, पटना : ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में 90 लाख गरीबों को छत मयस्सर नहीं है। केंद्र सरकार 2022 तक सभी को आवास देने का दावा कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से इंदिरा आवास योजना में राज्य का कोटा घटा रही है, उससे लक्ष्य पूरा होने में 35-40 वर्ष लग जाएगा। वह विभाग की ओर से 5510.06 करोड़ की मांग पर वाद-विवाद के बाद सरकार का जवाब पेश कर रहे थे। उन्होंने सदन को बताया कि स्वयं सहायता समूहों को दो प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। मंत्री

विधानसभा में बोले ग्रामीण विकास मंत्री

◆ केंद्र लगातार कर रहा कटौती, लक्ष्य पूरा करने में लगेगे 35-40 साल, स्वयं सहायता समूहों को दो प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा ऋण



ने कहा कि 2012-13 में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 6.86 लाख इंदिरा आवास का लक्ष्य रखा था, जिसे लगातार घटाया गया। 2015-16 के लिए मात्र 2.33 लाख इंदिरा आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जीविका के माध्यम से गांवों की महिलाओं को

आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जारी है। बीपीएल परिवार की महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें स्वरोजगार मुहैया कराया जा रहा है। अब तक 4.60 लाख स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं। 2017-18 तक हम दस लाख स्वयं सहायता समूह बनाएंगे।